foreign programme, so that reimbursement may be available from World Bank and US Aid agencies; and

(d) what percentage of reimbursement received from World Bank or US Aid agencies is allocated to the State of Madhya Pradesh and whether Government propose to consider allocating the full reimbursement money to the State of Madhya Pradesh in order to help the State in the early completion of the Scheme?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) Presuming that the question pertains to Madhya Pradesh the requisite information is given in the Statement enclosed. (*See* below).

(b) Government of Madhya Pradesh has to provide adequate matching funds to the externally assisted projects as per the agreements with aid agencies. However, most of the projects are behind schedule; constraint of funds being one of the reasons.

(c) No, Sir.

(d) 70 per cent. and no change is proposed.

Statement

Name of Aid Agency	Name of the Project	Project Cost (Rs. in Million)	Balance Cost (Rs. in Million as on 1-04-87)	Amount of assistance. (in Million)	Credit closing date	Disbursement as in March' 87 (In Mil.)	Remarks
WORLD BANK	M.P. Major Irrigation Project	5583.50	2598.24	US $ 220	30-6-87	US $ 106.02	Extension being sought
do.	M.P. Medium Irrigation Project	3960.10	1893.22	US $ 140	31-3-87	US $ 78.95	do.
IFAD	Do.			US $ 25.06	31-3-87	US $ 18.69	do.
WORLD BANK	M.P. Chambal Phase-II Project	759.60	240.40 (1-1-87)	US $ 31.00	31-3-87	US $ 17.92	do.
USAID	M.P. Minor Irrigation Project	812.50	573.29	US $ 46.00	30-9-89	US $ 2.05	
Federal Republic of Germany	TAWA CAD Project	1130.00	71.00	Ln. 45DM@ Grant 30 DM	31-3-81	DM 14.61 DM 29.30	Being continued

@ Deutsche Mark

Progress of irrigation projects in M.P.

4142. SHRI KESHAVPRASAD SHUKLA: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) how many major, medium and minor irrigation schemes are in progress in Madhya Pradesh and what is their balance cost an balance potential as on 1st April, 1987;

(b) whether the amount provided in the Seventh Plan is enough to complete them within the Seventh Plan period and if not by when the existing ongoing irrigation schemes are likely to be completed; and

(c) if the funds are inadequate, whether Government propose to provide special Central assistance to Madhya Pradesh over and above the State Plan ceiling for the completion of the schemes early?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): (a) 24 major and 40 medium irrigation projects with an estimated balance cost of about Rs. 3162 crores and a balance potential of about 15.4 lakh ha. are in progress. Such information regarding minor irrigation schemes is not maintained at the Centre.

(b) The outlays provided in the VII Plan are not adequate to complete all the ongoing projects. Three major and 13 medium projects for which outlays match spill-over costs are likely to be completed in the VII Plan. The completion of balance projects depends upon the priority given by the State Government for allocating adequate resources.

(c) No, Sir.

सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि के लिए सरकारी आवास का आवंटन

4143. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सामाजिक कार्यकर्ता, नर्तकों, लेखकों, कवियों के नाम क्या हैं जिन्हें दिल्ली में मफ्त सामान्य किराये पर, बाजार किराये पर या पूर्ण किराए के आधार पर आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उस मकान में वे कब से रह रहे हैं ;

(ख) क्या स्वतंत्रता सेनानियों, आजीवन सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों के लिये कोई आवास उपलब्ध कराये गये हैं ; यदि हां, तो कब से तथा कहां पर ; और

(ग) क्या इस प्रकार की आवासीय सुविधाय राजनीतिक दलों को भी प्रदान की गई हैं ; यदि हां, तो इन दलों के नाम क्या हैं और इन्हें किन स्थानों पर और कब से आवास प्रदान किये गये है तथा क्या ये आवास किराया आधार पर या पट्टे के आधार पर प्रदान किये गये हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं और यदि यह किराया आधार पर हैं तो किराये के रूप में कितनी राशि वसूल की जाती है ;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : एक विवरण संलग्न है । आवास का आवंटन लाइसेंस फीस के आधार पर किया गया है न कि पट्टे के आधार पर । [देखिए परिशिष्ट CXLIII, अनुपत्र संख्या 162]

दिल्ली में दूध की आवश्यकता

4144. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के महानगरीय शहर में दूध की दैनिक आवश्यकता कितनी है, इस नगर की दूध की आवश्यकता की पूर्ति के लिये क्या प्रबंध किये गए हैं ; दूध की कुल सप्लाई में गाय और भैंसों के कच्चे दूध और आयातित दूध पाऊडर तथा बटर आयल से तैयार किए गये दूध का कितना-कितना हिस्सा है;

(ख) क्या यह सच है कि यहां सभी प्रकार के दूध की इतनी ज्यादा कमी है कि दूध से तैयार होने वाले मिष्ठानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई प्रयास किये हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री यागेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।